

from airports in North Bengal was 2,351, out of which 462 take-offs were delayed beyond 30 minutes and 98 cancelled, due to the following reasons:—

| Sl. No. | Reasons | No. of Delays | No. of Cancellations |
|---------|------------------------|---------------|----------------------|
| 1. | Weather .. | 41 | 20 |
| 2. | Consequential | 347 | 63 |
| 3. | Miscellaneous .. | 12 | 1 |
| 4. | Air Traffic Control .. | 4 | 4 |
| 5. | Engineering .. | 33 | 5 |
| 6. | Traffic and Catering | 13 | 5 |
| 7. | Operations .. | 9 | — |
| 8. | Transport .. | 3 | — |
| | Total .. | 462 | 98 |

पटना हायर सेकेण्डरी स्कूल में उर्दू तथा बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा का विना जाना

* 715. श्री राम भवतार शाली : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने अक्टूबर 1961 में इस आशय का आदेश जारी किया था कि पटना हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा राज्य के अन्य स्कूलों में जिनमें उर्दू तथा बंगाली बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 60 हो, उर्दू तथा बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जिनमें ऐसे विद्यार्थियों को उपर्युक्त भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से स्कूल उपर्युक्त आदेशों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं और सरकार को भी इस बात की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) बिहार सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने 13-3-67 को आदेश दिया था कि भाषाई अल्पसंख्यकों को हार्ड स्कूलों की ऊंची चार श्रेणियों में गैर-भाषा विषय उनकी मातृभाषा में पढ़ाए जाएं, बशर्ते कि कम से कम 60 छात्र या 15 छात्र 8 वीं श्रेणी में प्रारम्भिक स्तर पर उस भाषा को अपनी मातृ भाषा के रूप में लें। आदेशों में यह भी स्पष्टतया कहा गया था कि व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण निर्णय को क्रमिक रूप से कार्यान्वित किया जाय।

(ख) पटना के राजकीय बहुउद्देशीय स्कूल में जनवरी 67 से लेकर 1968 की गर्मियों की छुट्टियों तक उर्दू और बंगाली माध्यम से शिक्षा दी गई। स्टाफ की कमी के कारण, संबंधित शिक्षकों को वापिस बुला लिया गया। राज्य सरकार के पास अतिरिक्त पदों के लिये एक प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). जैसा कि ऊपर कहा गया है, राजकीय स्कूलों से प्रारम्भ करके योजना का विस्तार क्रमिक रूप से करना था, किन्तु आर्थिक तंगी के कारण राज्य सरकार आवश्यक अतिरिक्त पदों को अस्तित्व में ला सकी है और न ही इस उद्देश्य के लिये सहायता प्राप्त स्कूलों के लिये अधिक अनुदान मंजूर कर सकी है फिर भी राज्य सरकार अतिरिक्त पदों को अस्तित्व में लाने के लिये प्रस्ताव की जांच कर रही है।

राज्य लाटरियों द्वारा उत्पन्न समस्याएं

* 716. श्री रघुबीर सिंह शाली : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों से उत्पन्न समस्याओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन समस्याओं को हल करने के लिये और विभिन्न लाटरियों में समानता लाने के लिये विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार किस तरीके से इन समस्याओं को हल करना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) लाटरी चलाने वाली राज्य सरकारों ने लाटरियां चलाने के लिए अपने-अपने नियम तथा विनियम बनाये हैं और उनको चलाने के लिए संतोषजनक व्यवस्था करना उनका काम होगा । किन्तु उत्तरी क्षेत्रीय परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इस विषय पर विचार किया था और बहु सहमत थी कि सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक होनी चाहिए और राज्य लाटरियां चलाने के लिए कुछ समान सिद्धांत तैयार किये जाने चाहिये ।

जहां तक किसी राज्य लाटरी टिकटों की, दूसरे राज्य में उसकी सहमति के बिना, बिक्री का सम्बन्ध है, उसके लिए उपयुक्त विभाग बनाया जा रहा है ।

Pay Scale of Teachers in Himachal Pradesh

*717. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state: .

(a) whether it is a fact that the Himachal Pradesh Government have recommended Kothari Commission grades to be given to Himachal Pradesh teachers;

(b) if so, whether the Central Government have accepted the recommendation and if not, the reasons therefor;

LB(N)7LSS-4(a)

(c) whether it is also a fact that while the Central Government are agreeable to give Central grades to Himachal Pradesh teachers, a condition has been imposed that no increase in existing salaries should be allowed;

(d) whether this condition is being opposed by the teachers; and

(e) the points which are still in dispute and how long will it take for Government to decide the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN): (a) Yes, Sir. Proposals relating to revision of pay-scales of the teachers were received.

(b) The Government have sanctioned revised scales to School teachers at par with corresponding categories of Delhi Teachers. As regards College Principals and teachers, the U.G.C. pay-scales have been extended to them.

(c) In the matter of pay-fixation in the revised scales, it has been decided that the pay of school teachers in revised pay-scales may be fixed in such a manner that total emoluments remain the same.

(d) Yes, Sir, representation has been received from one District Union of school teachers.

(e) The manner of pay-fixation of school teachers in the revised pay scales is being reconsidered. Every effort will be made to arrive at a decision as early as possible.

दिल्ली से आसाम को जाने वाली पार्श्व (नेटरल) सड़क परियोजना का निर्माण कार्य

*718. श्री भोलूह प्रसाद : क्या नौबहन तथा परिबहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के वर्ष 1954 के आदेश के अनुमरण में दिल्ली से आसाम को जाने वाली पार्श्व (नेटरल) सड़क परियोजना का निर्माण कार्य 1965 में हाथ में लिया गया था ; और